विवरण	1991-92+	1992-93+
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान :		
नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान	12,27,673.57	14,49,886.54
निरीक्षण शुल्क	20,265.00	21,583.00
	12,47,938.57	14,71,469.54
कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय :		
शिक्षण शुल्क	63.00	45,467.70
कर्मचारी चिकित्सा व्यय/निदेशक चिकित्सा व्यय	13,12,807.40	15,14,658.60
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,53,092.05	2,08,043.40
छुट्टी यात्रा रिआयत	2,70,915.65	4,12,882.20
परिवहन आर्थिक सहायता	77,954.95	3,20,156.70
कर्मचारियों की वर्दिया	76,915.80	1,24,865.50
समूह बीमा योजना	1,10,906.40	51,732.00
परोपकार निधि	10,248.00	7,526.00
	20,12,903.25	26,85,332.10
यात्रा तथा वाहन	18,28,815.15	10,79,020.34
कार्यालय भवन का अनुरक्षण	26,66,556.05	34,22,256.43
कार्यालय भवन का किराया	4,23,345.60	2,26,393.60

+ये आकड़ अनान्तम हैं तथा लेखा परीक्षा के अध्यधीन है।

करघों को दिये गये ऋण की धनराशि में वृद्धि करने के लिए अनुरोध

2715. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथ-करघा उद्योग के तहत स्थापित विभिन्न करघों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं से एक पूर्व निर्धारित राशि देने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में संस्थान द्वारा उनके पुनर्जीवन के लिए प्रति करघा अधिकतम कितनी धनराशि दी जा सकती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस धनराशि के लिए अधिकतम सीमा, 1983 में निर्धारित की गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1983 से 1993 की अवधि के दौरान आम मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनों के मूल्यों में उक्त अवधि के दौरान अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(च) क्या सरकार ने उक्त संस्थान को ऋण की राशि में तदनुसार वृद्धि करने के लिए कोई निर्देश दिया है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वकट स्वामी) : (क) राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिए स्थापित/वर्तमान प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान उनके अनुमानित उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है जो फिर प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अग्रिम कार्यशील पूंजी देते हैं ।

(ख) नाबार्ड द्वारा साधारणतया पुनर्वित्त उस विशेष वर्ष के प्रत्याशित उत्पादन के 40% के बराबर उपलब्ध होता है बशर्ते गत वर्ष कुल उत्पादन का कम से कम 60% विक्रय किया गया हो ।

(ग) जी नहीं । पुनर्वित्त के मानदंडों की समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

(घ) और (ङ) 1980-81=100 को आधार मानते हुए मैंच, 1993 में सूती और सिंथेटिक वस्त्र मशीनरी का अन्तरिम मूल्य 184.7 है । 1980-81 =100 को आधार मानते हुए मार्च, 1993 के अन्त में हथकरघा कपड़े का थोक अनुमानित मूल्य 216.5 है ।

(च) चूंकि प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाना सहकारी समितियों के प्रत्याशित उत्पादन पर आधारित होता है और ऐसा अनमान लगाया जाता है कि गत वर्ष की तुलना में वद्धि दर 20% से भी अधिक है इसलिए ऋण की राशि भी वर्ष-वार बढ़ने की आशा होती है ।

Announceent of Garment export entitlement policy

2716. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item "Exim changes worries Textile Ministry" and "High price 'Throttling' small garment exporters" under the heading "India" which appeared in A.T.A. Journal of June-July 1993 published from Hong Kong;

(b) if so, what is Government' reaction thereto; and

(c) by when the New Garments Export Entilement Distribution Policy for 1994-95 will be announced to take care of such problems of small Garments Exporters?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) As regards the news item captioned "Exim changes worries Textile Ministry", Ministry of Textiles had received certain representations from some exporters against some of the changes in the latest Export Import Policy/Procedures. This Ministry has taken up such issues with the Director General (Foreign Trade).

The thrust of the report captioned "High Price throttling small garment exporters" is that additional quantities be made available in respect of categories 340 and 341/USA. However, as the utilisation in these categories is very high, further rrleases in these categories is not possible.

(c) The new Garment Export Entitlement Distribution Policy is expected to be annouced shortly.